पंजीकृत संख्या 72/54–55 || वन्दे मातरम्|| Tel. 0141-2362212
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

प्रहलाद शर्मा	उमरावलाल वर्मा	देवलाल गोचर
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	महामंत्री
मो. 94140–56109	मो. 94148–52027	मो. 94144–03756

ज्ञापन प्रारूप

माननीय.....

.....

.....

विषय : पी.पी.पी. मोड पर विद्यालय चलाने के विरोध में ज्ञापन।

महोदय

उक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा **शिक्षक दिवस 05 सितम्बर 2017** को 300 विद्यालयों को पी.पी.पी. मोड में संचालित किये जाने के निर्णय किया है। संगठन इस निर्णय का घोर विरोध करता है।

लोक कल्याणकारी राज्य का प्राथमिक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था करें। पी.पी.पी. मोड में विद्यालय संचालन के निर्णय से यह स्पष्ट है कि सरकार अपने दायित्व निर्वहन से विपरीत कर निजीकरण को बढ़ावा देने जा रही है। इससे निश्चित रूप से बाजारी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। बाजार केवल आर्थिक हितों का चिन्तन करता है। **बाजारी शक्तियों को शिक्षा व संस्कारों से कोई सरोकार नहीं है।** शिक्षा के बाजारीकरण से सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों तथा इन विद्यालयों में सेवा देने वाले शिक्षकों का आर्थिक शोषण होने की सर्वाधिक सम्भावना है।

सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत कर मात्रात्मक रूप में शिक्षा का प्रसार किया था। सरकार से अब यह अपेक्षा थी कि सरकार इन विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा का प्रसार करेगी तथा भौतिक एवं मानवीय संसाधन की दृष्टि से विद्यालयों को समृद्ध करेगी **किन्तु सरकार का यह कदम दर्शाता है कि सरकार अपने उत्तरदायित्व से बचना चाह रही है।** विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी और समाज की भागीदारी से राजस्थान के शिक्षा विभाग में गत तीन वर्षों में उल्लेखनीय कार्य हुए है जिनका पूरे भारत में 'शिक्षा का राजस्थान मॉडल' के तहत सरकार विविध मंचों पर डंका बजा रही है। परन्तु सरकार की प्रस्तावित पी.पी.पी. मोड की नीति इन उपलब्धियों को छलावा घोषित कर रही है।

अतः राजस्थान के विद्यालयों को पी.पी.पी. मोड में देने के इस प्रतिगामी कदम को तत्काल वापस लिये जाने के सम्बन्ध में आप अपने प्रभाव का उपयोग कर माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार से अनुरोध करते हुए शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी के हित में सकारात्मक योगदान करें।

आदर सहित।

भवदीय

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

in'k dk;dkfj.kh cBd fnukd 10-09-17 d fu.k;kuqlkj ihihih ekM d fojks/k e mDr Kkiu viu {k= d lHkh tuifrfuf/k;k dk fn;k tkuk gA